Statement on AIDS in India

485. SHRI INDER KUMAR GUJRAL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to an announcement made by Prof. Rager Short of Monash Unviersity, Melbourna in the Conference titled Australian Foreign Ecologically Sustainable Population, India will be worst affected AIDS region in five years time;

(b) whether Government have examined the basis of the aforesaid statement made by Prof. Short; and

(c) the steps Government are contemplating to meet the explosion likely to be caused in the field of AIDS?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A.R. ANTULAY): (a) and (b) A news item to this effect has appeared in the Pioneer, New Delhi, dated March 5, 1995. The Statement attributed to Prof. Rager Short could at best, be his assumption.

(c) In order to prevent and control the spread of HIV/AIDS in India a comprehensive programme is currently under implementation as a centrally sponsored scheme throughout the country. The strategies of the programme consist of generation of awareness amongst high risk behaviour groups and general public about HIV/AIDs, control of Sexually Transmitted Diseases, Blood Safety and rational use of blood, better survellance; and diagnosis and Clinical Management of HIV/AIDS cases.

ग्रामीण क्षेत्रों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाना

486. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों के 1,25,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु खादी ग्रामोद्योग आयोग ने देश में 125 ब्लाकों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने ब्लाक हैं और ऐसे ब्लाकों की पहचान हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये थे;

(ग) क्या रोजगार उपलब्ध कराने हेतु शुरू किये जा रहे कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर कुल कितनी धनराशि व्यय किये जाने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (ग्रामीण रोजगार और गरीबी उपशमन विभाग) (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जी हां।

(ख) देशभर में चुने गए खण्डों की राज्यवार संख्या विवरण में संलग्न संख्या है। **(नीचे देखिए)** खण्डों की चुनते समय संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले पिछड़े खण्डों की प्राथमिकता दी गयी है।

(ग) जी हां

(घ) इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित समय-सीमा 1994-95 से तीन वर्षों के लिए है। प्रति खण्ड 3.00 करोड़ रुपये के अनुमोदित निवेश की आवश्यकता है, जिसे खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी एवं वित्तीय संस्थाओं के बजटीय समर्थन से पूरा किया जाना है।

विवरण

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चुने गए ब्लाकों की राज्य-वार संख्या

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र	चुने गए खण्डों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	10
2.	असम	5
3.	अरूणाचल प्रदेश	1
4.	बिहार (पटना)	11
5.	गुजरात	6